CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

बारामूला जिला डेयरी उत्पादन में नई श्वेत क्रांति का नेतृत्व करता है

उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले ने एक उल्लेखनीय बदलाव का अनुभव किया है, जो नोटबंदी के बाद डेयरी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ एक नई "श्वेत क्रांति" का प्रतीक बन गया है। जिला अब प्रतिदिन 5.5 लाख लीटर से अधिक दूध का उत्पादन करता है, जो कि पहले की दूध की कमी वाली स्थिति से एक उल्लेखनीय बदलाव है।

केवल चार साल पहले, बारामूला में पशुपालन विभाग को अपर्याप्त दूध उत्पादन की चुनौती का सामना करना पड़ा था। हालाँकि, एक प्रतिबद्ध समुदाय ने बदलाव की योजना बनाई है, जिससे बारामूला डेयरी क्षेत्र में सबसे आगे हो गया है। सोपोर और पट्टन जैसे क्षेत्रों की उर्वरता इस परिवर्तन को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण रही है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जून संस्करण के दौरान बारामूला की प्रगति की सराहना की। उन्होंने नेहलपोरा, पट्टन से स्नातक इशरत नबी को उनके अग्रणी डेयरी उद्यम 'मीर सिस्टर्स डेयरी फार्म' के लिए बारामूला की महिलाओं की सराहना की। इशरत का फार्म रोजाना लगभग 150 लीटर दूध बेचता है, जो प्रेरणा की किरण बनकर खड़ा है।

ओडिशा सरकार ने पैक्स को बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों में बदलने के लिए कदम उठाए हैं

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) की भूमिका बढ़ाने और उनके संचालन में बहुमुखी प्रतिभा लाने के लिए एक रणनीतिक कदम में, ओडिशा राज्य सरकार ने सहकारिता विभाग को बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के रूप में विकास के लिए संभावित PACS की पहचान करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव प्रदीप जेना के नेतृत्व में राज्य की सहकारी विकास समिति ने निर्णय लिया कि जिला सहकारी विकास समितियाँ उपयुक्त पैक्स का चयन करेंगी और प्रत्येक के लिए विविध व्यावसायिक गतिविधियों को नामित करेंगी।

सहकारिता मंत्रालय के मॉडल उपनियमों के तहत, राज्य द्वारा संशोधनों के साथ अनुकूलित, पैक्स को डेयरी, मत्स्य पालन, अनाज भंडारण और ईंधन बिक्री सहित 25 से अधिक व्यवसायों में शामिल होने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, PACS दीर्घकालिक ऋण ऋण प्रदान करेगा, नियुक्ति केंद्र बनेगा और सामान्य सेवा बिंदुओं के रूप में कार्य करेगा। वर्तमान में, 492 PACS सामान्य सेवा नेटवर्क का हिस्सा हैं।

असम का पशु चिकित्सा विभाग 700 करोड़ रुपये के सुधार के साथ परिवर्तन के लिए तैयार है

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य के पशु चिकित्सा और पशुपालन विभाग में व्यापक बदलाव का आह्वान किया है। विभाग, जिसे अक्सर उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, पुनरुद्धार के लिए तैयार है क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसके आधुनिकीकरण के लिए 700 करोड़ रुपये का पर्याप्त बजट आवंटित किया है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में, प्रत्येक पशु चिकित्सा उप-केंद्र को अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए 25 लाख रुपये मिलेंगे।

राज्य में वर्तमान में पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के तहत 421 पशु औषधालय, 767 उप-केंद्र, 19 रोग निदान प्रयोगशालाएं, 61 अनुदेशात्मक फार्म, 17 जमे हुए वीर्य भंडार और 10 प्रशिक्षण केंद्र हैं। इसके महत्व के बावजूद, विभाग ने एलओसी घोटाले सहित चुनौतियों का सामना किया है। यह परिवर्तनकारी कदम राज्य की कृषि-केंद्रित पहचान के साथ जुड़कर असम के पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्रों को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं रखता है।

डेयरी उद्योग और किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया

डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने पुनर्गठित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) का अनावरण किया है। फरवरी 2014 में शुरू की गई इस दूरदर्शी योजना को अब 2021-22 से 2025-26 तक चलाने के लिए नए जोश के साथ तैयार किया गया है।

घटक 'ए': गुणवत्ता मानकों और बुनियादी ढांचे को ऊपर उठाना एनपीडीडी का पहला पहलू, जिसे उचित रूप से घटक 'ए' नाम दिया गया है, गुणवत्ता वाले दूध परीक्षण उपकरण और प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए शीर्ष बुनियादी ढांचे के निर्माण और सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है। इस उन्नयन से राज्य सहकारी डेयरी संघों और जिला सहकारी दूध उत्पादक संघों से लेकर स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), दूध उत्पादक कंपनियों और किसान उत्पादक संगठनों तक हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को लाभ होगा।

घटक 'बी': सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना किसानों की आय बढ़ाने और उनकी बाजार भागीदारी को समृद्ध करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, एनपीडीडी योजना का घटक 'बी' "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" पर केंद्रित है। यह गतिशील पहल नौ राज्यों, अर्थात् बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में संचालित होती है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) ऋण के रूप में उल्लेखनीय 924.56 करोड़ रुपये सहित 1568.28 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ, इस पहलू का उद्देश्य संगठित बाजारों तक किसानों की पहुंच का विस्तार करना, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना है। , और विपणन बुनियादी ढांचे को बढ़ाएं।
दो विशिष्ट घटकों के साथ, इस योजना का लक्ष्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, बाजार तक पहुंच बढ़ाना और प्रसंस्करण सुविधाओं को उन्नत करना है, इस प्रकार डेयरी उत्साही लोगों के लिए एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।

स्थानीय उत्पादन में वृद्धि के बीच डेयरी उत्पादकों ने दूध पाउडर के आयात को रोकने का आह्वान किया है

3 अगस्त को कृषि मंत्री महिंदा अमरवीरा के साथ एक बैठक में, स्थानीय डेयरी उत्पादकों ने दूध पाउडर के आयात को बंद करने का जोरदार आग्रह किया है। यह आह्वान इस वर्ष स्थानीय दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के आलोक में आया है, जो उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

3 अगस्त को कृषि मंत्री महिंदा अमरवीरा के साथ एक बैठक में, स्थानीय डेयरी उत्पादकों ने दूध पाउडर के आयात को बंद करने का जोरदार आग्रह किया है। यह आह्वान इस वर्ष स्थानीय दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के आलोक में आया है, जो उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

घरेलू डेयरी क्षेत्र पिछले दो वर्षों से पशु आहार की कमी और आर्थिक संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रहा था, जिसके परिणामस्वरूप गिरावट आई। हालाँकि, अब स्थिति बदल गई है, सरकारी स्वामित्व वाली डेयरी कंपनियों, मिल्को और राष्ट्रीय पशुधन विकास बोर्ड (एनएलडीबी) के साथ-साथ निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाली पेलवट्टा डेयरी कंपनी, स्थानीय दूध उत्पादन में वृद्धि का अनुभव कर रही है।

जवाब में, मंत्री ने कृषि मंत्रालय के पशुधन प्रभाग के अधिकारियों को दूध उत्पादन में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। दूध पाउडर के आयात पर फैसले के लिए रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश की जाएगी।

मिल्को, जिसने पिछले दो वर्षों में तरल दूध की कमी के कारण दूध पाउडर और हाईलैंड जमे हुए दूध का उत्पादन रोक दिया था, ने इस साल उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है। इसके साथ ही, एनएलडीबी ने अपने सभी डेयरी उत्पादों का उत्पादन बढ़ा दिया है, जो इस क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव का संकेत है।

दूध और दुग्ध उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर करने की कोई योजना नहीं ये कहना है केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार, 1 अगस्त, 2023 को कहा कि दुग्ध उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि दरें जीएसटी परिषद की सिफारिश पर आधारित हैं।

अति-उच्च तापमान वाले दूध के अलावा, पहले से पैक और लेबल किए गए रूप में बेचे जाने वाले दही, लस्सी, छाछ और पनीर जैसे दुग्ध उत्पादों पर 5% की रियायती जीएसटी लगाई जाती है। इसके अलावा, गाढ़ा दूध, मक्खन, घी और पनीर पर 12% का जीएसटी लागू होता है। ये जीएसटी दरें सभी राज्यों में समान रूप से लगाई जाती हैं।

श्री चौधरी ने कहा कि ताजा दूध और पाश्चुरीकृत दूध को जीएसटी से छूट दी गयी है. दरें जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं

दूध और दूध उत्पादों पर जीएसटी को कम करने या खत्म करने की योजना पर राज्यसभा सदस्य कनिमोझी सोमू के एक सवाल पर, मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद से इस तरह के प्रस्ताव के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई थी।

मंत्री ने यह भी कहा कि डेयरी किसानों के लिए व्यापक वित्तीय पैकेज का कोई प्रस्ताव नहीं है। पशुपालन और डेयरी विभाग राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और पशुधन स्वास्थ्य सहित विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

निवारक उपायों पर ध्यान केंद्रित करने से जैविक डेयरी गायों का स्वास्थ्य बेहतर होता है

जैविक डेयरी गायों से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी चर्चाएं अक्सर अनुमोदित उपचारों की जटिल सूचियों से प्रभावित होती हैं। सीआरओपीपी कोऑपरेटिव/ऑर्गेनिक वैली के डॉ. गाइ जोडार्स्की ने उपचार आवश्यकताओं को कम करने के लिए, बछड़ों से लेकर गायों तक, मिट्टी से लेकर चारे तक, समग्र पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया। रोकथाम पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक मजबूत प्रणाली कई मुद्दों को रोकती है। मिट्टी, पौधों और गायों के जटिल सूक्ष्म जीवों पर विचार करते हुए, इसका आधार स्वस्थ मिट्टी का पोषण करना है।

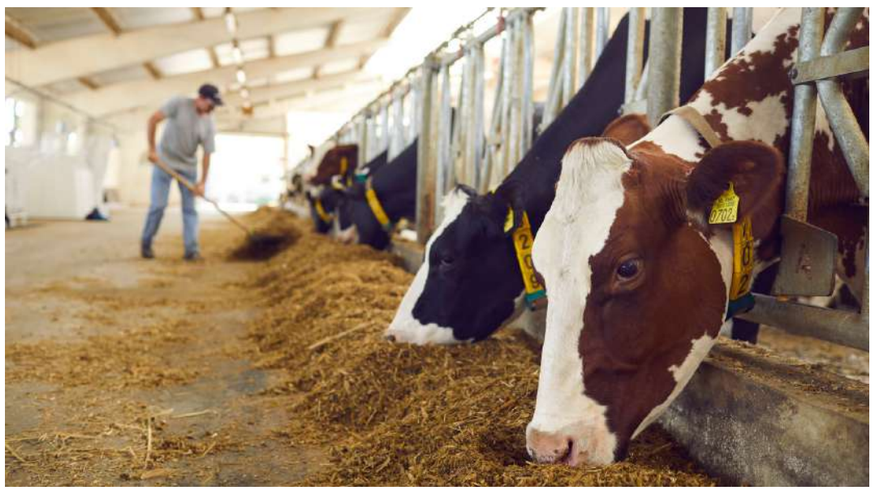

विविध रोपण और चराई के अंतराल आवश्यक हैं, साथ ही गोबर बीटल जैसे कीड़े भी हैं जो खाद को तोड़कर परजीवी जोखिम को कम करते हैं। मवेशियों के घूमने से कृमि का जोखिम कम हो जाता है, विशेष रूप से बछड़ों के लिए उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है। टीके, कोलोस्ट्रम खिलाना और दूध पिलाना परजीवी नियंत्रण में सहायता करता है।

डॉ. जोडार्स्की ने संक्रमित बछड़ों को मारने, रोकथाम पर जोर देने और साक्ष्य-आधारित आपातकालीन उपचार का आग्रह करने की सलाह दी। ब्लोट के लिए ठंडा मक्खन और कीटोसिस के लिए सेब साइडर सिरका सहित जैविक उपचार का उपयोग किया जा सकता है। यद्यपि प्रमाणित जैविक सामग्री को प्राथमिकता दी जाती है, आपात्कालीन परिस्थितियाँ अन्य विकल्पों की अनुमति देती हैं। उन्होंने रोकथाम की प्रभावकारिता को रेखांकित करते हुए पारंपरिक गायों की तुलना में जैविक गायों में कम चिकित्सीय हस्तक्षेपों का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि एनडीडीबी मुख्य प्रवर्तक होगा और इन उत्पादों का विपणन अमूल ब्रांड के तहत किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर उत्पादों के विपणन के लिए एक नए ब्रांड का भी अनावरण किया जाएगा।

हम कौन हैं?

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) के तत्वावधान में काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था "भारत में डेयरी कौशल के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CEDSI)", किसानों की आजीविका के सशक्तिकरण और बेहतरी में मदद करने के लिए, वेतनभोगी कर्मचारी, और डेयरी मूल्य श्रृंखला में अन्य हितधारक।

सीईडीएसआई सदस्यता उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं, विकास चिकित्सकों, डेयरी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और किसानों को डेयरी उद्योग के लिए आसन्न महत्व के मुद्दों पर बहस और चर्चा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी।